[Dr. Subramaniam Swamy]

Railways and Air India are the worst offenders. The State Government has minimised the destitution by creating a Slum Board. I demand the creation of a National Slum Improvement Board to provide basic amenities for poor people of the city of Bombay and other towns.

(xii) SUPPLY OF CEMENT AND COAL FOR RAJASTHAN CANAL PROJECT

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : राजस्थान नहर देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, यह देश की सब से बड़ी नहर होगी जो प्रतिवर्ष 31 लाख टन अनाज उत्पन्न कर देश की हरित क्रान्ति में एक नया कीतिमान स्थापित करेगी । परन्तु केन्द्रीय सरकार की असहनीय धीमी गति ने इस योजना का काम ठप्प कर दिया है । न तो इसे सीमेंट उपलब्ध किया है और न कोयला, पिछले 1979—80 में कोयला न मिलने के कारण 9 करोड़ की धनराशि लेप्स हो गई । पिछले वर्ष 1 लाख 90 हजार टन कोयला मिलना था, केवल 19 हजार टन कोयला ही बड़ी मेहरबानी से मिला, इस वर्ष पिछले 9 महीनों में 72 रेक कोयला मिलना था, केवल 8 रेक कोयला आज तक उपलब्ध किया गया और राजस्थान को इस के लिए केवल मांग की 50 प्रतिशत सीमेन्ट मिली है । किस तरह यह योजना पूरी होगी, इस के लिए कौन दोषी ठहराया जायेगा, इस का उत्तर भविष्य ही देगा । मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि वह युद्ध स्तर पर राजस्थान कैनाल को आवश्यक कोयला व सीमेंट दे कर इस के बढ़ते हुए प्रगति के चरण नहीं रुकने दे ।

(xiii) ECONOMIC CONDITION FOR WEAVERS

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि आज देश में बुनकरों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है । बुनकर शोषण के शिकार हैं । उन्हें पर्याप्त ऋण भी नहीं दिया जाता जिस से कि अपना काम सुचारु रूप से कर सकें । सूत और कैमिकल्स की कीमतों के बढ़ने से बुनकरों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है जिस से हथकरघा उद्योग के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । सूत के मूल्य के बढ़ने का कारण नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के बहुत से कारखानों द्वारा सूत का न बनाया जाना भी है । अतः सरकार को शीघ्र यह निर्देश देना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने सूत का उत्पादन करें जिस से सूत का मूल्य कम हो सके, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बुनकरों को सूत और कैमिकल्स उपलब्ध कराये जांय और उन्हें पर्याप्त ऋण दिया जाय ताकि वे अपना कारोबार प्रभावी ढंग से चला सकें । इस सम्बन्ध में बैंकों को उचित निर्देश तत्काल दिये जाने चाहिए ।

(xiv) UNDERSTAFFING OF TELEGRAPH OFFICES

SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirapalli): I would draw the attention of the House to the understaffing of Telegram offices throughout India in general, and Tiruchirapalli division in particular. The shortage of staff in the telegraphist cadre is so alarming that many circuits/working stations are being kept unmanned for a very long time, causing heavy delay in transmitting important telegrams and consequently telling upon the efficiency of the service.

For example, Tiruchirappalli office has at present a sanctioned strength of 59 telegraphists. If the recommendations of the staff inspection unit, appointed by the government in 1974 is given effect to, then this strength has to be increased to 69. Shortage of 10 telegraphists accounts to 10 x 6.7-67 manhours is not at all compensated by recruitment of additional staff. Apart from this there is understaffing due to shortage, and inadequate leave reserve and impractical standards for calculation of staff sanction.

I demand sanction of staff on a more rational and practical basis. Staff should be sanctioned on circuit